

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,  
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक : 27 सितम्बर, 2016

विषय- सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, नैनीताल में अधिवक्ताओं के चैम्बर्स/लाइब्रेरी निर्माण किये जाने हेतु 75 वर्गमीटर भूमि लीज पर दिये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-793/UHC/Admin.B/X-b/2005, दिनांक 27.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जिला न्यायालय, नैनीताल के परिसर में स्थित 75 वर्गमीटर भूमि को अधिवक्ताओं के चैम्बर्स/लाइब्रेरी निर्माण किये जाने हेतु प्रीमियम रहित नामिनल रेंट (Nominal Rent) रु0-1.00 प्रतिवर्ष लीज पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृति की गयी है।
2. प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग स्वीकृति के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
3. यदि प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित न्याय विभाग को वापस की जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
4. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)  
सचिव।

संख्या- 115 / (1)/XXXVI(3)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल।
2. अध्यक्ष/सचिव, जिला बार संघ, नैनीताल।
3. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)  
अपर सचिव।